

यूनिवर्सिटी में नहीं गये और न इस के लिए उन्होंने समय लगाया। अगर वे वहाँ गये होते तो महीने रूप में क्या हो रहा। यह उन्हें मालूम हो जाता। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि कितना समय अभी और लगेगा इस चुकन्दर में चीनी बनाने में और इस की जाच पड़ताल पर, क्योंकि मुद्दे से यह बात कही जा रही है और श्रीमन्, मैं देख आया हूँ और मैं उस विश्व-विद्यालय से संबंधित रहा हूँ। मैंने अपनी आँखों से देखा है कि वहाँ क्या हो रहा है और लार्ज स्केल पर इस के प्रोडक्शन की कोई बात हो रही है या नहीं यह मैं जानना चाहता हूँ।

MR. CHAIRMAN : Mr. Minister, you please answer.

SHRI ANNASAHEB SHINDE : I can only inform the hon. Member with all humility that I myself had been to Pant Nagar, and even before replying to this question we have got the necessary material from Pant Nagar. I seek the hon. Member's co-operation and request him not to misunderstand on every matter.

SHRI A.G. KULKARNI : May I know from the Minister whether in the present circumstances a long-term planning on better land use as well as conservation of water are more important for any production pattern to be fixed and, in view of that, it is only a pious hope in the Ministry of Agriculture that beet will be taken up? The hon. Minister has rightly pointed out that a sugar factory which is crushing beet has got to depend on a different technology where fuel is also not going to be available. Then, will commensurate physical profits be given to the growers as well as the crushers? Otherwise this hope will only remain a hope for another 15 years or so and nothing will come forth. I want a categorical reply from the Minister as to what he proposes to do.

SHRI ANNASAHEB SHINDE: As far as water requirement is concerned, for beet production also water requirement is equally heavy. So, there water economy is not likely to be advantageous. On the other aspects, as I have already indicated, there are some encouraging signs but still there are many areas in sugar production from beet on which we will have to come to definite conclusions. Still, the data is not very positive; we have to wait for some time.

शिक्षा के लिये स्वतंत्र व्यवस्था

* 182. श्री जगदीश प्रसाद माथुर :†

श्री पीताम्बर दास :

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

श्री लाल श्रद्धाणी :

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी :

श्री धीरेन्द्र कुमार सखलेचा :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सर्वोदय नेता आचार्य विनोबा भावे ने यह सुझाव दिया है कि न्याय-पालिका के समान शिक्षा के लिये भी एक स्वतंत्र व्यवस्था होनी चाहिए, और

(ख) यदि हा, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उसके अनुसार क्या कार्यवाही की गई है?

‡[INDEPENDENT SET UP FOR EDUCATION

*182. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR :

SHRI PITAMBER DAS :

SHRI J. P. YADAV :

SHRI LAL K. ADVANI :

SHRI O. P. TYAGI :

SHRI V. K. SAKHLECHA :

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Jagdish Prasad Mathur.

‡[] English translation.

Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the Sarvodaya Leader Acharya Vinoba Bhave has suggested that there should be an independent set-up for education like that of judiciary; and

(b) if so, what is the reaction of Government in this regard and what action has been taken in pursuance thereof ?]

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (PROF. S. NURAL HASAN): (a) According to press reports Acharya Vinoba Bhave, while addressing the delegates to the All India National Education Conference, who had assembled at Paramdham Ashram, Paunar, to hear his views on education, said that education should be made independent like judiciary.

(b) Government respects the academic freedom of teachers, including the right to speak and write about national and international issues. But this is not incompatible with the duty of the State to provide facilities for education, maintain its quality and to take steps to promote equality of educational opportunity and the welfare of the weaker sections of the community or to develop education in a manner which will contribute to national development.

†[शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार, आचार्य विनोबा भावे ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के प्रतिनिधियों के सम्मुख, भाषण करने हुए, जो उनके विचार सुनने के लिए परमधाम आश्रम, पाँनर में एकत्र हुए थे, यह कहा था कि न्यायपालिका के समान ही शिक्षा को भी स्वतंत्र किया जाना चाहिए।

†[] Hindi Translation.

(ख) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर बोलने और लिखने के अधिकार महान् अध्यापकों की शैक्षिक स्वतंत्रता का सरकार सम्मान करती है। किन्तु यह बात शिक्षा के लिए मृत्विधियों की व्यवस्था करने उसकी किम्मत बताए रखने तथा शैक्षिक अवसरों में समानता को बढ़ावा देने तथा समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए कदम उठाने अथवा शिक्षा का इस तरीके से विकास करना जिसमें वह राष्ट्रीय विकास में मद्दायक हो सके, के राज्य के कर्तव्य से असंगत न होनी चाहिए।]

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : श्रीमन् हममें मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप यह मवाल देखे, यह हिन्दी में किया गया है और मन्त्री महोदय हिन्दी बहुत अच्छी जानते हैं और ये जबाब दे रहे हैं अंग्रेजी में। अगर उत्तर प्रदेश के मन्त्री ऐसा करेंगे तो श्रीगो से क्या आशा की जा सकती है। आप श्रीमन् हमने विद्वान हैं, आप कैसे गाय देने हैं अंग्रेजी में बोलने की।

श्री सहायपति : गाय देंगे, आप बैठ जाइए।

श्री जगदीश प्रसाद साधु : मैं समझता हूँ मन्त्री महोदय की जानकारी में यह बात होगी कि वर्तमान शिक्षा पद्धति की जो व्यवस्था है, शिक्षा देने की, कुछ स्थानों पर केन्द्रीय सरकार के हाथ में कुछ है, कुछ स्थानों में प्रान्तीय सरकार के हाथ में कुछ है, कुछ स्थानों में उसमें भी ज्यादा नीचे स्तर पर जाकर हमने डिमेन्ट्राइजेशन किया, पचायत समिति, पचायत लेबल पर, और हर स्थान में शिक्षा संचालन का एड्मिनिस्ट्रेशन अलग अलग है, और इस कारण से हर स्तर के ऊपर क्या इस प्रकार का अनुभव आया है, इस प्रकार की शिक्षाएँ हुई हैं चाहे दिल्ली युनिवर्सिटी का मवाल हो, चाहे किसी गाँव का मवाल हो, कि पंच से लेकर प्रधान मन्त्री तक शिक्षा के बारे में जो व्यवस्था है, एड्मिनिस्ट्रेशन उसमें हस्तक्षेप करते हैं और शिक्षाविदों का उसमें हाथ न होकर उन दोनों पक्षों का उसमें हस्तक्षेप रहता है।

प्रो० एस० नुरुल हसन : जनाबेवाला, यह एक बहुत जेनरल किस्म का ध्यान माननीय सदस्य

ने दिया। जो भी किमी यूनिवर्सिटी का मामला हो या स्कूलों का मामला हो, हर यूनिवर्सिटी के लॉज के मुताबिक उसका इंतजाम होता है। उसी तरह से स्कूलों के मिलमिले में लॉज बने हुए हैं, बल्क बने हुए हैं और उनके तहत इनजाम होता है और अगर किसी जगह पर किसी पटि-बुलर कानून के खिलाफ किसी ने दखलअदाजी की है और अगर उस मामले का केन्द्रीय सरकार से संबंध है, तो मुझे अगर बताया जाएगा, तो मैं जरूर देखूंगा उसमें हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए, वरना यह कहना कि किमी तरह का हस्तक्षेप होता है इस बात को मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ और खाम तौर पर जो प्रधान मंत्री का नाम लिया है, इसके लिए मैं खुद गवाही दे सकता हूँ मेरे डेल्टा में कोई ऐसा केस नहीं है जिसे प्रधान मंत्री ने इंटरफेयर किया हो।

डा० भाई महावीर : क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के मामले में नहीं किया ?

श्री जगदीश प्रसाद साधुर : इसी संबंध में एक दूसरा सवाल शिक्षा की व्यवस्था की दृष्टि से करना चाहता हूँ। आपने विभिन्न समय पर विभिन्न कमिशन नियुक्त किए हैं लेकिन फिर भी इस व्यवस्था के नाते में एकरूपता नहीं आई और मुख्य रूप से जो शिक्षा प्रदान करने वाले हैं उनके संबंध में कोई सम्माननीय स्थिति बनाने की दृष्टि से हमारा विभाग असफल रहा है। अगर इंजीनियरों ने 4 दिन स्ट्राइक कर दी तो सारी गवर्मेंट की मशीनरी उसमें हिल जाती है, उनसे समझौता करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अगर शिक्षक बहुत जबरदस्त आंदोलन अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर करे और अगर सरकार द्वारा निर्धारित बातें जो तय कर दी गई हैं उनको लेकर भी शिक्षक आंदोलन करें—मैं केवल हरियाणा का उदाहरण नहीं देना चाहता मैंने देश भर में भी अगर आपके शिक्षक असंतुष्ट रहे—तो क्या सरकार की मान्यता है कि हमारे छात्रों को उसी प्रकार से शिक्षा दी जा सकती है ?

श्री सभापति : यह आप सवाल पूछ रहे हैं क्या ? आप सवाल करिए . .

श्री जगदीश प्रसाद साधुर : तो क्या आपके पास सारी शिक्षा व्यवस्था को रीऑर्गेनाइज करने की कोई योजना है ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : हुजूरें वाला, मैं जिस कुर्सी में इस वक़्त यहां पर आपके सामने हाजिर हूँ, इस हाउस में मैं नहीं आ सकता था अगर मैं उस को एक्सेस करने बक़्त सविधान की शपथ ग्रहण न करता। सविधान में तो साफ लिखा है कि शिक्षा राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और इसमें मिवाय इसके कि हम यह कोशिश करें कि तमाम राज्यों के मंत्रियों की बैठक बुलाये और उसमें एक यूनीफार्म पालिसी इवाल्फ करें। इस मामले में केन्द्रीय सरकार का कोई दखल नहीं हो सकता है। अब इस मिलमिले में, इस सदन ने नेशनल पालिसी रिजोल्यूशन आफ एजुकेशन मंजूर किया है। 1968 में और इस चीज को सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड फार एजुकेशन ने भी मंजूर किया है। अभी पिछले मिनट्स में इस बोर्ड की फिगर बँटक हुई थी और बहुत सी बातों के ऊपर यह तय किया गया कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें एक यूनीफार्म पालिसी पर चलेगी। हमारी और मेरी मन्त्रालय की यह कोशिश है कि कि जो बात सब लागू मंजूर करे उसके ऊपर अमल दरासद करने की कोशिश की जाय और और इस चीज में दखल देने का मेरा खयाल नहीं है।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या वह यह अनुभव करने हैं कि देश के वातावरण में जातीयता, प्रांतीयता, मकीर्णता, साम्प्रदायिकता का बहुत बड़ा दूषित वातावरण इस समय देश में पनप रहा है और हर एक प्रांत की शिक्षा संस्थाओं में ऐसा वातावरण प्रवेश कर चुका है। आज गवर्नमेंट के जो स्कूल आर कालेज हैं, उनमें पढाई का स्तर बिल्कुल निम्न हो गया है और इसलिए लोग अपने बच्चों को प्राइवेट और पब्लिक स्कूलों में भेजने लगे हैं। आपने देश में सब लोगों को समान शिक्षा देने की बात कही है, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि सब लोगों को एक सांस्कृतिक भावना,

एक देशभक्ति की भावना की शिक्षा दी जा सके, तो क्या वर्तमान शिक्षा प्रणाली को उसका स्वतन्त्र स्वरूप रखते हुए उसमें कोई परिवर्तन करने का विचार है या नहीं ? यदि हा, तो वह क्या है ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : माननीय सदस्य ने जो बात कही है, मैं उनकी भावना से सहमत हूँ कि किसी तरह से भी कोई ऐसा एजुकेशन इस्टीमेशन नहीं होना चाहिये जिसमें एक हिन्दुस्तानी की तरफ से तालीम के जरिये दूसरे हिन्दुस्तानी के खिलाफ नफरत पैदा की जाय या किसी तरह से नफरत का जजबा पैदा किया जाये ।

श्री श्रीम प्रकाश त्यागी : मैं तो जातीयता और प्रान्तीयता की बात कर रहा हूँ ।

प्रो० एस० नूरुल हसन : मैं यही कह रहा हूँ किसी हिन्दुस्तानी के खिलाफ किसी दूसरे हिन्दुस्तानी की तालीम में नफरत का जजबा फैलाने की बात नहीं हो और जो इस तरह की कोशिश करता है, तो यह निहायत अफसोस की बात है और उसका मुकाबिला करना चाहिये । लेकिन इस मिलमिले में जो नीति है और एजुकेशन कमिशन ने जो सिफारिश की है, उन पर सेन्ट्रल एडवाइजरी कमेटी ने बराबर विचार किया है । यह एक मानी हुई नीति है कि इस तरह की बातों के खिलाफ हम सब को मिलकर कोशिश करनी चाहिये । मुझे यकीन है कि राज्य सरकारें जहाँ कहीं भी एजुकेशन मिस्टम में इस तरह की चीजें हैं, इस तरह की भावना है, उनके खिलाफ अपने पूरे आरगनाइजेशन सेट अप का इस्तेमाल करेंगी ।

श्री श्रीम प्रकाश त्यागी : मैंने सवाल पूछा था कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सरकार का कोई परिवर्तन करने का विचार है या नहीं ? यदि है, तो वह क्या है ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : हुजूर वाला इस बारे में सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड ने कनई कुछ फैसला किया है और उसकी रिपोर्ट एवेलेबिल है । माननीय सदस्य

उम रिपोर्ट को देख सकते हैं । हमारी यह कोशिश है कि पंचवर्षीय योजना में उस फैसले के मुनाबिक अमल दरामद कराया जाय ।

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON :

Sir, in view of the fact that education is a powerful instrument for social transformation and has to be used as such and in view of the fact that the functions of the judiciary are to maintain *status quo* and interpret the laws passed by the Parliament does the Government not consider the suggestion that the execution of education should be left to an authority independent of Parliament and the people, to be a reactionary suggestion and that such suggestion would not be entertained by the Government at all in future also ?

PROF S NURUL HASAN .

In my principal answer, I have already stated about the responsibility of the State and this is not a question of the individual opinion of my Ministry only. It has the approval in the form of the National Policy Resolution of the Parliament. Then there are certain compulsions on the State which are given in the Directive Principles of the State policy and, therefore, it is quite right that the State has to play a role. The State cannot say that we have no role to play. The only limited point I was submitting is that the State in this case means a State Government primarily. Although we can help in bringing them together, I do not wish to give the impression to any one that the Government of India in the Ministry of Education has any intention of issuing directives or orders to State Governments. We want to work together with them. We are confident that they share our feelings and sentiments and it is a question of evolving a common pattern and uniform values as far as possible. In this I have always found that the State Governments are co-operative.

SHRI SHYAM LAL GUPTA : There is so much control on primary institutions that they cannot function independently although it is seen that privately controlled institutions impart better education. Will the Education Minister think of removing the unnecessary interference in the working of these institutions ? It is the responsibility of the Central to see that there is uniformity of syllabi and that standards are maintained throughout the country.

PROF. S. NURUL HASAN : It is a matter of opinion. I do not think there is any unnecessary interference and I do not subscribe to that view at all.

DR. R. K. CHAKRABARTI : Like the Judicial Service and Administrative Service, is the Government thinking of setting up an Indian Educational Service, so that it will help create mobility help in the exchange of ideas and curb regionalism ?

PROF. S. NURUL HASAN : There is no such proposal under consideration.

श्री भइया राम मुण्डा : सभापति महोदय, मैं बिहार से आया हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वहाँ आदिवासियों के बीच रोमन कैथोलिक बहुत स्कूल चलाता है और उन स्कूलों में...

श्री सभापति : आप प्रश्न कीजिए।

श्री भइया राम मुण्डा : उन स्कूलों में काम करने वाले फादर मदर ब्रदर तथा मिस्टर्स होते हैं और उनकी अलग पंजाक होती है और वे आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करने में लगे हुए हैं। ऐसे जो शिक्षक हैं उनको सरकार की ओर से तलब दी जाती है। क्या ऐसे लोगों को सरकार अपने फंड से वेतन देना वाछनीय समझती है ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : जनाबे वाला, सविधान की धारा 30(1) के मुताबिक हर माइनारिटी की चाहे वह ग्लिजन् के आधार पर हो या भाषा के आधार पर हो, एजुकेशनल इस्टीमेट्स-

शन कायम करने का मुकम्मिल अधिकार है और इसी धारा की उपधारा (2) के मुताबिक यह राज्य का फर्ज है कि जब वह ग्रांट दे तो उसमें इस बिना पर किसी इम्पियाज को न करे कि यह सस्था माइनारिटी ने बनाई है। यह पोजीशन विलकुल क्लियर है।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : सभापति महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है मन्त्री जी यह कहकर सविधान की आइ में छिप रहे हैं कि सविधान में माइनारिटी को भी अधिकार है स्कूल कायम करने का और यह भी अधिकार है कि उनको ग्रांट दी जाए मगर क्या माइनारिटी को यह अधिकार है कि वह किसी का धर्म परिवर्तन करे ?

श्री सभापति : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। This is no point of order please. I rule it out.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : सभापति महोदय, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है। मेरा पाइंट ऑफ आर्डर यह है कि सविधान की धारा के अनुसार मैक्यूलर स्टेट में किसी भी शिक्षा सस्था को अपने धर्म का शिक्षण देने का अधिकार नहीं है।

MR. CHAIRMAN : This is no point of order. A point of order must relate to the procedure in the House.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : आपने कम्प्टीशन के खिलाफ जवाब दिया है।

श्री भइया राम मुण्डा : सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री सभापति : आप बैठ जाइये, जवाब हो गया।

DR. BHAI MAHAVIR : I only want to submit that the question related to conversion. But the answer has not touched that.

श्री सभापति : डा० भाई महावीर, आप बैठ जाइये। That does not arise out of this.

डा० भाई महावीर : वह पूछ रहे हैं कि कनवर्शन करवाने के लिए सरकार की तरफ से उनको वेतन मिले, क्या यह उचित है ?

श्री सभापति : श्रीमती सीतादेवी, आप पृष्ठिये

श्रीमती सीता देवी : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि अभी मंत्री जी ने कहा है कि हर एक माइनारिटी का मविधान के मुताबिक अधिकार है .

श्री सभापति : आप का जो सवाल है उसके ऊपर पूछिये ।

श्रीमती सीता देवी : मैं मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहती हूँ कि जा सांप्रदायिक शिक्षण संस्थाएँ इस प्रकार की शिक्षा देती हैं जो कि बच्चों में गैरी नेशनल स्प्रिट पैदा करती हैं

(Interruptions)

MR CHAIRMAN That does not arise out of this I rule it out of order.

डा० भाई महावीर श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री से लेकर छोटे से छोटे शिक्षा अधिकारी तक यह बहुत बार कहा गया है कि हमारी शिक्षा पद्धति दोषपूर्ण है और पिछले कई वर्षों से हम यह सुन रहे हैं, तो वह दोष क्या है जिसकी तरफ सकेत करते हुए शिक्षा पद्धति को दोषपूर्ण कहा गया है ? उसको कौन दूर करेगा और कब दूर करेगा ? क्या यह दोष भी वह ध्यान में रखते हैं कि आज का शिक्षक अपने आपको सबसे उपेक्षित महसूस करता है ? जैसा मेरे साथी कह रहे थे कि इंजीनियर चार दिन की हड़ताल करे तो सरकार हिल जाती है और शिक्षक हजारों की संख्या में पकड़े जाते हैं .

MR CHAIRMAN : That does not arise out of this, Dr. Bhai Mahavir.

डा० भाई महावीर : मैं पूछना चाहता हूँ कि शिक्षा-पद्धति दोषपूर्ण है यह बात बार-बार कही जा चुकी है । तो क्या यह दोष सरकार के ध्यान में है कि आज का शिक्षक मोस्ट नेग्लेक्टेड अपने आपको महसूस करता है और उसका सबन यह है कि हजारों शिक्षक रोज जेल जायें तो भी सरकार उस से मम नहीं होती ।

प्रो० एस० नूरुल हसन : मान्यवर, शिक्षा-पद्धति में क्या-क्या खराबियाँ हैं इसका जवाब देने में एक घंटा से ज्यादा निकल जाएगा अगर कोई आदमी इन की कांशिश करे लेकिन सरकार की जो नीति है और वह नेशनल पालिसी में लिखी हुई है । उसके अलावा मेट्रन ऐडवाइजरी बोर्ड आफ एजुकेशन की जा अभी मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने अपनी पालिसी बनाई है और हम यह कांशिश कर रहे हैं कि जिस हद तक हो सके, पाचवी पंचवर्षीय योजना में इसके ऊपर अमल दरासद करा दिया जाए ।

जहां तक टीचर्स का सवाल है, अगर आप इजाजत दें तो मैं दो-चार जुमले पढ़ दूँ नेशनल पालिसी में जिसको पार्लियामेंट ने भी गजूर किया है

“Of all the factors which determine the quality of education and its contribution to national development the teacher is undoubtedly the most important. It is on his personal qualities and character, his educational qualifications and professional competence that the success of all educational endeavour must ultimately depend Teachers must, therefore, be accorded an honoured place in society”

यह पालिसी हमारी सरकार की भी है और पार्लियामेंट भी उसमें शरीक है । यह पालिसी हम बिल्कुल वाजेंद कर चुके हैं । इसमें कार्ट रफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है ।

डा० भाई महावीर : मेरे सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं आया ।

श्री सभापति : आ गया आप का जवाब ।

डा० भाई महावीर : मैंने कहा कि यह जो दोष है इसे कौन दूर करेगा ।

श्री सभापति : सारे डिटेल्स मैं बताना नहीं सकता ।

डा० भाई महावीर : सवाल यह है कि खाली इसमें लिखकर के क्या सरकार समझती है कि काम हो गया ।